राजस्व/ लोकवित्त (Public Finance)

बजट का वर्गीकरण
(Classification of Budget)

बजट वर्गीकरण

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बजट के महत्त्व को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि बजट संबंधी लोक व्यय एवं राजस्व के आंकड़ों को ऐसे व्यवस्थित ढंग से रखा जाए कि उनका समस्त अर्थ महत्त्व स्पष्ट हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट का वर्गीकरण जरूरी हो जाता है।

बजट वर्गीकरण के प्रकार

बजट का वर्गीकरण कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है; जैसे-

- क्रियात्मक वर्गीकरण
- संगठनात्मक वर्गीकरण
- विषय संबंधी वर्गीकरण
- आर्थिक वर्गीकरण
- प्रोग्राम तथा निष्पादन वर्गीकरण

THE ECONOMICS GURU

क्रियात्मक वर्गीकरण (Functional Classification)

बजट को विधायिका के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि मुद्रा का आवंटन ऐसे ढंग से हो ताकि सरकार की इच्छाओं को पूरा करना आसान हो जाए।
यह बजट का व्यय पक्ष है। राजस्व पक्ष में इस बात पर ध्यान देना पड़ता है करके बाहर का वितरण सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो।

अर्थशास्त्र के सभी विषयों एवं कक्षाओं के नोट्स, प्रश्नोत्तर, सैंपल पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नपत्र (हिंदी या अंग्रेजी माध्यम) के PDF आपको www.theeconomicsguru.com पर मिल जायेंगे।

इसके साथ ही सभी हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए Free **LIVE CLASS** भी उपलब्ध है, हमारे **YOUTUBE CHANNEL "THE ECONOMICS GURU"** पर । अभी **subscribe** कर लीजिये और ज्यदा से ज्यादा **शेयर** कर दीजिये अपने दोस्तों के बीच।

किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते है, YOUTUBE के कमेंट बॉक्स में कमेन्ट करें या वेबसाइट के Email वाले Option में जाकर **Email** करे या WhatsApp कर सकते है (Website में लिंक दिया गया है।

धन्यवाद

नकुल ढाली

The Economics Guru

लाभार्थी बोर्ड:

CBSE, UK Board, UP Board, Bihar Board, MP Board, CG Board, Rajasthan Board, Haryana Board

साथ ही **BA; B.COM; MA** के सभी SEMESTER लिए भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।

अभी VISIT करें www.theeconomicsguru.com

Subscribe my **YOUTUBE** channel **THE ECONOMICS GURU**

Follow me:

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

Facebook- *Nakul Dhali*

Instagram- *@dhalinakul*

बजट के यह उद्देश्य उस समय पूरे हो सकते हैं जब लोक व्यय का वर्गीकरण प्रदत्त सेवाओं के आधार पर किया जाए। इसे **क्रियात्मक वर्गीकरण** कहा जाता है।

उदाहरण:

- **सामान्य लोक सेवाएं** (प्रतिरक्षा न्याय पुलिस तथा सामान्य प्रशासन)
- **सामुदायिक सेवाएं** (सड़क एवं पुल सफाई आदि)
- **सामाजिक सेवाएँ** (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य)
- **आर्थिक सेवाएँ** (कृषि, खनन, निर्माण, बिजली, परिवहन, संचार आदि।)

लोक व्यय की ही तरह राजस्व का भी वर्गीकरण होता है। जैसे-

- **कर राजस्व** आयकर, निगमकर, बिक्री कर आदि।
- **गैर कर राजस्व।**

क्रियात्मक वर्गीकरण सामान्य लेन देन का उनके उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण है। *इस वर्गीकरण का उद्देश्य यह देखना होता है कि सरकारी आय को सर्वोत्तम लाभ के लिए खर्च किया जाता है।* ऐसे वर्गीकरण से उन उद्देश्यों के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती है जिन्हें लोक व्यय के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए सरकारी प्रोग्राम तथा क्रिया को उनके द्वारा प्रदत्त आधारभूत सेवाओं के अनुसार वर्गों में बांटा जाता है।

THE ECONOMICS GURU

संगठनात्मक वर्गीकरण (Organisational Classification)

इसके अंतर्गत सरकार के संगठनात्मक इकाइयों (जैसे विभागीय मंत्रालय) के अनुसार बजट को बांटा जाता है। ये इकाइयाँ ही सरकार की **कार्य करने वाली इकाइयां** कहलाती है। ये ही बजट प्रोग्राम की योजना बनाती है तथा उन्हें कार्यान्वित भी करती हैं।

भारत में अनुदान मांग को संसद के समक्ष मंत्रालय के अनुसार रख जाता है। लोक व्यय का इस प्रकार वर्गीकरण काफी आसान है, किंतु राजस्व पक्ष कठिनाइयां प्रस्तुत करता है।

विषय-संबंधी वर्गीकरण (Object Classification)

लोक व्यय का वर्गीकरण व्यय करने वाली एजेंसियों के अनुसार हो सकता है जिससे संगठनात्मक या एजेंसी वर्गीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण के साथ विषय भी जोड़े जा सकते हैं।

वर्कहेड का कहना है कि विषयानुसार वर्गीकरण उस युग की देन जब विधायकों तथा नागरिको को प्रशासकों पर विश्वास की कमी थी।

इस प्रकरण के दौरान बजट व्यवस्था में लेखा पद्धति का समावेश किया गया ताकि गबन पर अंकुश रखा जा सके। लोक व्यय के संबंध में **उदाहरण-**

- कार्मिक क्षतिपूर्ति
    - *पूर्णकालिक स्थयी स्थान*
    - *अन्य स्थान*
    - *अन्य कार्मिक क्षतिपूर्ति*
- कार्मिक लाभव्यक्तियों का यात्रा एवं परिवहन
- वस्तुओं का परिवहन
- संचार, उपयोगिताएं तथा लगान
- मुद्रण एवं पुनरुत्पादन
- अन्य सेवाएँ
- आपूर्ति एवं सामग्री
- साज सामान
- अनुदान, सब्सिडी तह दान

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

आर्थिक वर्गीकरण (Economic Classification)

यह एक ऐसा वर्गीकरण है जिसके अनुसार लोक व्यय तथा राजस्व को आर्थिक वर्गों के अनुसार बांटा जाता है।

इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की क्रिया पर सरकारी लेनदेन के अल्पकालिक प्रभाव का विश्लेषण करना है।

सरकारी लेनदेन के आर्थिक एवं क्रियात्मक वर्गीकरण से सभी आर्थिक आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। ये आंकड़े आर्थिक नीति निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।

राष्ट्रीय लेखा के सिलसिले में भी आर्थिक वर्गीकरण का महत्व है विकास योजनाओं के निर्माण में भी इसकी उपादेयता है।

उदाहरण:

(i) चालू व्यय

- वस्तुओं और सेवाओं पर वे
- मजदूरी और वेतन।
- अन्य खरीद
- ब्याज का भुगतान
- सब्सिडी तथा अन्य चालू स्थानांतरण।

(ii) पूंजी व्यय

- नए एवं विद्यमान स्थिर पूंजी परिसंपत्ति की प्राप्त।
- स्टॉक की खरीद।
- भूमि तथा अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद।
- पूंजी हस्तांतरण।

(iii) शुद्ध उधार

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

(iv) ज्ञापन मदद

- घरेलु व्यय
- विदेशों में व्यय
- घरेलु उधार
- विदेशों में उधार

प्रोग्राम एवं निष्पादन वर्गीकरण: बजट नव-प्रवर्तन

1950 की दशक की एक महत्वपूर्ण देन है, प्राय: सभी देशों में योजनाओं का अपनाया जाना। इस संदर्भ में पारंपरिक बजट व्यवस्था अधिक उपयोगी नहीं रह पाती है। इस बजट में नवप्रवर्तन की आवश्यकता होती है।
इसी नव प्रवर्तन का परिणाम है प्रोग्राम तथा निष्पादन वर्गीकरण।

निष्पत्ति या निष्पादन बजट

(Performance Budget)

निष्पादन बजट का संबंध मुख्य रूप से संगठन यह संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों या लक्ष्यों से होता है।

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

इस नवीन प्रणाली में बजट को प्रवाधित धनराशि का विधि उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है तथा यह दर्शाया जाता है कि विभिन्न क्रिया एवं क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों के लिए किस प्रकार धनराशि का विनियोजन हो।

श्री ए प्रेमचंद के अनुसार, "निष्पादन बजट एक प्रक्रिया है जिसमें राजकीय सक्रियाओ को कार्यों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को एक संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है"।

घोष एवं गुप्ता के अनुसार, "निष्पादन बजट एक तकनीक है जिसमें सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को उसकी क्रियाओं, कार्यकलापों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निष्पादन बजट किसी भी संख्या या संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने से संबंध रखता है बजाय विभिन्न उद्देश्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि से"।

अन्य शब्दों में,

निष्पादन बजट प्रणाली में बजट में प्रावधान धनराशि का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। इस बजट प्रणाली में यह दर्शाया जाता है कि विभिन्न प्रक्रियाओं एवं कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों के लिए किस प्रकार धनराशि का प्रयोग हो।

निष्पादन बजट की प्रकृति/ उद्देश्य या विशेषताएं

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

- व्यय के प्रावधान और योजना में दर्शाए हुए कार्यक्रमों, के वर्गीकरण में एकरूपता लाना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति का भविष्य में किए जाने वाले वित्तीय प्रावधनों से संबंध जोड़ना।
- विकास की दिशा में किसी प्रकार प्रगति हो रही है उसका सही-सही निर्धारण करना ताकि विदेशी योजनाओं के कार्यक्रमों के महत्त्व को देख कर आवश्यकतानुसार प्रावधनों में परिवर्तन संभव हो सके।

- निष्पादन अंकेक्षण का कार्य साधक बनाना।
- वार्षिक बजट तथा विकास योजनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- योजना में निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्यों की उपलब्धि का माप करना।

इस प्रकार के बजट को तैयार करने में पूर्व महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करना अनिवार्य है, जैसे-

- क्या उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर लिया गया है?
- क्या इस धनराशि को व्यय करने के पश्चात जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा?
- क्या इस धनराशि को जनता से एकत्र करने में सामाजिक लागत तो अधिक नहीं आई है?

निष्पादन बटन का महत्व

भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने देश में निष्पादन बजट प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी। आयोग का मत था कि इस प्रकार के बजट न केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने चाहिए अपितु समस्त राज्य सरकार को भी इसी प्रणाली को लागू कर देना चाहिए। इस प्रणाली को व्यापारिक क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INFORMATION | KNOWLEDGE

निष्पादन बजट तकनीक प्रबंधन को विभिन्न निर्णयों को लेने में निम्न प्रकार से मदद करती है-

- यह तकनीक निष्पादन में सुधार हेतु **'उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध'** को लागू करने में मदद करता है।

- यह तकनीक संस्था द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले वैकल्पिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की पहचान एवं मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं।
- यह तकनीक विभिन्न विभागों को कोषों के आवंटन को तर्कसंगत आधार प्रदान करने उनके निष्पादन की माप को प्रभावित बनाती है।

इस प्रकार निष्पादन बजट नियोजन, बजटन, लागत, लेखांकन, कर प्रतिवेदन एवं नियंत्रण पद्धतियों को एकीकरण कर प्रबंधक को को भविष्य की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है।

निष्पादन बजट की सीमाएं

निष्पादन बजट की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है-

- निष्पादन बजट का प्रमुख केंद्र सरकारी कार्यकलापों को उसके कार्यक्रम तथा गतिविधि के आधार पर वर्गीकृत करना है। लेकिन आज के इस व्यवहारिक युग में इतना साफ सुथरा व पूर्व संगठित वर्गीकरण संभव नहीं है।
- निष्पादन बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को केवल परिणामात्मक मूल्य ही हो पाता है, गुणात्मक मूल्यांकन नहीं।
- इस तकनीक की उपयोगिता उन क्षेत्रों में सीमित हो जाती है (जैसे पुलिस, कानून, शोध, प्रशासन आदि) जिसकी अंतिम परिणामों को मापा नहीं जा सकता।
- बजट बनाने का निर्णय लेते समय विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक मूल्यांकन में कठिनाई आती है। यह निष्पादन बजट में भी संभव नहीं हो पाता है, तब तक कि इसका अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों से नहीं जोड़ा जाए।

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

- निष्पादन बजट की सफलता के लिए यह जरूरी है। विभिन्न विभाग सुसंगठित हो तथा उसकी पहचान विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों के साथ हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं।
- विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लागत अनुमान के वर्गीकरण की प्रक्रिया काफी कठिन और अक्सर यह अनुमान इतने अर्थपूर्ण नहीं रहते हैं, जितने रहने चाहिए।
- निष्पादन बजट प्रक्रिया विभागों, संस्थाओं में व्याप्त कमियों को दूर नहीं कर पाती है।

शून्य-आधारित बजट

(Zero Based Budgeting)

शून्य-आधारित बजट (ZBB) क्या है?

शून्य-आधारित बजट (ZBB) एक बजट तकनीक है जो बजट इतिहास के बजाय दक्षता और आवश्यकता के आधार पर धन आवंटित करती है। प्रबंधन शुरुआत से शुरू करता है और एक बजट विकसित करता है जिसमें केवल व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक संचालन और व्यय शामिल होते हैं; ऐसे कोई खर्च नहीं हैं जो स्वचालित रूप से बजट में जुड़ जाते हैं।

EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

बजट में शामिल किए जाने के लिए सभी खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए , अगर कोई कंपनी वेतन और मजदूरी व्यय में ₹1,00,000 खर्च करने की उम्मीद करती है, और मानती है कि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे ₹1,00,000 की आवश्यकता है, तो इसे बजट में शामिल

किया जाएगा - हालाँकि, वेतन/मजदूरी के प्रत्येक व्यक्तिगत आवंटन की जाँच की जानी चाहिए और उसे शामिल करने के लिए उचित ठहराया जाना चाहिए।

भारत में शुन्य पर आधारित बजट को ***विज्ञानं और प्रद्योगिकी विभाग*** द्वारा 1983 में अपनाया गया था। 1986 में, भारत सरकार ने व्यय बजट निर्धारण करने के लिए शून्य - आधारित बजट प्रणाली को लागू किया। सरकार ने सभी मंत्रलयों के लिए अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा करना और शुन्य - आधारित बजट अवधारणा के आधार पर अपने व्यय अनुमान तैयार करना अनिवार्य कर दिया ।

परिभाषाएं

पीटर पायरेर- "शून्य पर आधारित बजटिंग एक संचालित नियोजन एवं बजटिंग प्रक्रिया है, जिसमे प्रत्येक मैनेजर के अपने सम्पूर्ण बजट प्रस्तावों का औचित्य शून्य से बताना होता है, तथा प्रत्येक मैनेजर पर सबूत का भार दाल दिया जाता है की उसे कोई धन क्यों व्यय करना चाहिये"।

जिमी कार्टर के अनुसार, "शून्य पर आधारित बजटिंग में बजट को इकाइयों में रखा जाता है जिसे 'निर्णय पैकेज' कहा जाता है और जो प्रत्येक स्तर पर मैनेजर द्वारा तैयार किये जाते है । यह पैकेज विभाग की विद्यमान या प्रस्तावित क्रियाओं को पूर्ण करते है।"

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

इन पैकेज में विश्लेषण के उद्देश्य, लागत, निष्पादन की माप लाभ व् कार्यों के वैकल्पिक प्रयोग तथा कार्य न करने के परिणाम, आदि सम्मिलित किया जाता है।

सभी पैकेजों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है।

विभागीय प्रमुख व प्रमुख अधिकारी से विचार विमर्श करने के बाद इन क्रमों को अंतिम रूप देकर इन पैकेजों को एक स्तर तक स्वीकार क्या जाता है।

शून्य आधारित बजट के महत्वपूर्ण कदम-

उद्देश्यों का मूल्यांकन: संगठन के विभिन्न उद्देश्यों व् लक्ष्यों को विस्तृत रूप से मूल्यांकित किया जाता है।

क्रियाओं का विश्लेषण- उद्देश्यों का व्यापक रूप से मूल्यांकन करने के बाद संगठन की विभिन्न क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। इससे विभिन्न कार्यों व क्रियाओं के महत्व के निर्धारण में सहायता मिलती है।

आवश्यक परिवर्तन - इस निर्धारण के आधार पर आवश्यक परिवर्तन लेन के प्रयास किये जाते है।

इकाइयों की पहचान - शून्य पर आधारित बजटिंग को प्रारंभ करने में इकाइयों की पहचान सरलता से की जा सकती है ।

निर्णय पैकेज - एक निश्चित स्तर की क्रियाओं की वित्तीय आवश्यकताओं हेतुं 'निर्णय पैकेज का सहारा लिया जता है जिसके लिए उद्देश्यों, क्रियाओं, वैकल्पिक साधान एवं कोषों का स्तर, आदि को ध्यान में रखा जाता है।

क्रम निश्चित करना - निर्णय पैकेज का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद उसका क्रम विभागीय अधिकारी द्वारा अपने उच्च प्रबन्धक को देना होता है।

बजट प्रस्ताव निश्चित करना - विभागीय स्तर पर क्रम निश्चित करने के बाद प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाता है।

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

शून्य-आधारित बजट बनाम पारंपरिक बजट

सभी व्यवसाय व्यय पर नज़र रखने और लागत को कम करने तथा लाभ को अधिकतम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए बजट का उपयोग करते हैं।

वर्तमान/अगले वर्ष के लिए बजट नियोजन आमतौर पर पिछले वर्षों के बजट पर आधारित होता है।

वास्तव में, पारंपरिक बजट पिछले वर्ष के बजट से शुरू होता है और आमतौर पर नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वृद्धिशील प्रतिशत वृद्धि या कमी को लागू करता है। ये प्रतिशत आमतौर पर 1% से 10% तक होते हैं।

कभी-कभी, बजट नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, या कुछ वर्षों में, समग्र बाजार दृष्टिकोण और अन्य बाहरी कारकों के आधार पर, काफी अधिक या कम लागत दिखा सकते हैं। ऐसे परिदृश्यों में, पिछले साल के बजट को देखना समझदारी नहीं है क्योंकि कंपनी की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पूरे बजट को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है - इसलिए, शून्य-आधारित बजट।

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

शून्य-आधारित बजट में, कंपनी व्यवसाय के हर खर्च/पहलू का एक-एक करके विश्लेषण करती है। इसे "शून्य आधार" से शुरू करना कहा जाता है। जबकि शून्य-आधारित बजट सभी खर्चों की जांच करता है, पारंपरिक बजट केवल प्रस्तावित नए खर्चों की जांच करता है।

शुन्य आधारित बजटिंग हेतु प्रमुख शर्तें

कठिन कागजी कार्य - शुन्य पर आधारित बजटिंग प्रक्रिया में कठिन कागजी कार्यवाही व् विस्तृत व्याख्या करना आवश्यक माना जाता है।

सूचनाएं उपलब्ध होना - संगठन इस स्थिति में होना चाहिए की वह सभी प्रकार की अपेक्षित सूचनाएं दे सकें, जिसमे लागत सम्बन्धी आंकडें भी सम्मिलित है।

अवधारणा की स्वीकृति - यह पद्धति उसी समय सफल हो पाती है जबकि इस बजट की अवधारणा को पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया जाए।

व्यक्तियों क व्यवहार- संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार इस बजटिंग के पक्ष में होना चाहिए अन्यथा योजना के कार्यों में प्राथमिकता का क्रम निश्चित करना कठिन होगा ।

शून्य-आधारित बजट के लाभ

- **अंतिम आउटपुट अच्छी** तरह से न्यायोचित है और कंपनी की समग्र व्यावसायिक रणनीति या व्यवसाय योजना के अनुरूप है।
- कंपनी भर में अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है
- मान्यताओं को चुनौती देकर और व्यय की जांच करके प्रदर्शन और परिचालन दक्षता में सुधार करता है
- पारंपरिक बजट में प्रतिशत वृद्धि से बचने से लागत में कटौती करने की काफी बेहतर संभावना होती है।

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

शून्य-आधारित बजट के नुकसान

- शून्य-आधारित बजट को लागू करने के लिए योग्य कर्मियों और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो समय लेने वाला और महंगा हो सकता है।

- कंपनी की समग्र संस्कृति या ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचा सकता है
- न्यूनतम उपलब्ध निधि वाली कंपनियों के लिए लागत निषेधात्मक हो सकती है (क्योंकि इसमें समय, शोध और विश्लेषण की आवश्यकता होती है)
- शून्य आधार से शुरू करना काफी जटिल और थकाऊ है। पारंपरिक बजट बनाना बहुत सरल, तेज़ और लागू करने में आसान है।

अर्थशास्त्र के सभी विषयों एवं कक्षाओं के नोट्स, प्रश्नोत्तर, सैंपल पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नपत्र (हिंदी या अंग्रेजी माध्यम) के PDF आपको www.theeconomicsguru.com पर मिल जायेंगे।
इसके साथ ही सभी हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए Free **LIVE CLASS** भी उपलब्ध है, हमारे **YOUTUBE CHANNEL "THE ECONOMICS GURU"** पर । अभी **subscribe** कर लीजिये और ज्यदा से ज्यादा **शेयर** कर दीजिये अपने दोस्तों के बीच।
किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते है, YOUTUBE के कमेंट बॉक्स में कमेन्ट करें या वेबसाइट के Email वाले Option में जाकर **Email** करे या WhatsApp कर सकते है (Website में लिंक दिया गया है।

धन्यवाद
नकुल ढाली
The Economics Guru

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

लाभार्थी बोर्ड:

CBSE, UK Board, UP Board, Bihar Board, MP Board, CG Board, Rajasthan Board, Haryana Board

साथ ही **BA; B.COM; MA** के सभी SEMESTER लिए भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।

अभी VISIT करें www.theeconomicsguru.com

Subscribe my YOUTUBE channel THE ECONOMICS GURU

Follow me:

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

Facebook- *Nakul Dhali*

Instagram- *@dhalinakul*

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE